गुजरात की आर्थिक विकास दर

3602. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोलाः** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात की आर्थिक विकास दर कितनी कम अथवा अधिक है;

(ख) सरकार ने, अन्य राज्यों के समान ही गुजरात की आर्थिक विकास दर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान, विभिन्न राज्यों की कुल विकास दर कितनी थी?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) से (ग) निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एन एस डी पी) में विकास के माध्यम से यथा अनुमानित गुजरात सहित राज्यों के आर्थिक विकास की दर विवरण के रूप में संलग्न है। **(नीचे देखिए)** विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत संरचना औद्योगिक तथा उद्यमशीलता के ऐतिहासिक रूप से असमान विकास, वर्ष-प्रति-वर्ष वर्षा में अन्तर तथा परिणामस्वरूप सूखा तथा बाढ़ जैसे विभिन्न कारणों से राज्यों के बीच निवल राज्य घरेलू उत्पादन (एनएसडीपी) में विकास अलग-अलग है। राज्य सरकारें राज्यों की आय बढ़ाने के लिए विकास योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं। केन्द्र सरकार एक फार्मूले के अनुसार राज्य योजनाओं के लिए सहायता प्रदान करती है, जिसमें प्रतिव्यक्ति कम आय वाले राज्यों को अधिक महत्व दिया जाता है।

विवरण

गत वर्ष की तुलना में सतत (1980-81) मूल्यों पर गुजरात सहित अन्य राज्यों के निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एन एस डी पी) की वार्षिक विकास दर

क्र.सं.	राज्य	1990-91	1991-92 (पी)	1992-93 (क्यू)	1993-94 (ए)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.6	1.1	(-) 0.7	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.5	4.9	—	—
3.	असाम	4.8	7.0	5.4	—
4.	बिहार	8.9	(-) 6.1	1.6	—
5.	गोआ	7.5	1.9	1.7	—
6.	गुजरात	0.8	(-) 3.9	14.6	—
7.	हरियाणा	9.1	1.7	5.1	—
8.	हिमाचल प्रदेश	0.5	(-) 0.7	—	—
9.	जम्मू और कश्मीर	3.0	3.7	4.1	—
10.	कर्नाटक	0.1	12.4	2.0	—
11.	केरल	7.7	6.4	7.4	7.7
12.	मध्य प्रदेश	19.2	(-) 7.4	2.5	—
13.	महाराष्ट्र	5.3	(-) 3.6	8.9	—
14.	मणिपुर	7.3	10.4	—	—
15.	मेघालय	11.8	11.4	7.5	—
16.	नागालैंड	(-) 0.9	3.2	—	—

1	2	3	4	5	6
17. उड़ीसा		(-) 10.4	11.4	(-) 2.8	—
18. पंजाब		1.8	4.9	4.1	(-) 6.9
19. राजस्थान		15.7	(-) 8.9	11.8	(-) 6.9
20. सिक्किम		10.1	—	—	—
21. तमिलनाडु		7.4	5.9	2.2	—
22. त्रिपुरा		5.4	—	—	—
23. उत्तर प्रदेश		5.6	1.4	1.0	—
24. प० बंगाल		2.9	5.9	4.3	—
उपादान लागत पर अखिल भारतीय निवल घरेलू उत्पाद		4.7	0.5	3.8	3.6

पी: अनन्तिम क्यू: तुरत अनुमान ए: प्रत्याशित

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार के माध्यम से संबंधित राज्य सरकार के आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय

बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता

3603. **श्री एस० आस्टिन:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री 25 अप्रैल, 1994 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 398 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, रोजगार सृजन करने पर कुल कितना धन खर्च किया गया;

(ख) क्या सरकार के पास बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मत्रांलय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) आर्थिक क्रिया-कलापों के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और उत्पादन के माध्यम से सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन किया जाता है। अनुपूरक उपाय के तौर पर अनेक विशेष रोजगार सृजन स्कीमें भी शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण विशेष रोजगार स्कीमों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार का बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता

(करोड़ रुपये)

	स्कीम	व्यय		
		1991-92	1992-93	1994-95 (अनंतिम)
1.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी)	773.09	693.08	950.07
2.	जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई)			
	प्रथम चरण	2659.89	2704.76	3580.82
	दूसरा चरण	—	—	216.91